



VISION IAS

www.visionias.in

11 SEP 2019

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1244)

Name of Candidate	Dinesh Kumar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	58740
Center	MP	Date	11-09-19

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. Discuss the need of an Independent Fiscal Council (IFC) in bringing about transparency and accountability in fiscal processes in India. (150 words) 10

भारत में राजकोषीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का समावेश करने हेतु एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद (IFC) की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

भारत में राजकोषीय घाटे की स्थिति को नियंत्रित करने तथा आर्थिक संतुष्टि को बनाए रखने हेतु स्वतंत्र राजकोषीय परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

→ वर्तमान में एफआरबीएल अधिनियम (FRBM)-2003 यद्यपि चतुर्खाता ~~का~~ द्वारा एवं राजकोषीय घाटे को 0 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत पर निर्धारित करता है परन्तु पूर्वतः इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

पारदर्शिता का समावेश :-

→ IFC लोकसुत्रावन नीतियों के त्वतंत्र होकर राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए निर्णय लेगी।

→ इसके निर्णय पारदर्शी तरीके से होंगे अतः जवाबदेही बढ़ेगी।

→ यह आयात-निर्मात, विदेशी निवेश, मुद्रा का वर्धिप्रवाह आदि से ध्यान में रखते हुए सरकार को सुझाव देगा कि अपत्तियों से बचा जा सके।

जवाबदेहिता का समवेश :-

→ IFC को भी RBI की वर्त पर लगातार तीम तिमिही तड वांदिता परिणाम प्राप्त नही होने पर सरकार को जवाब देना होगा।

→ IFC थुंकि विशेषतः शामिल होंगे अतः अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय बजट का समवेश तंतुन रखा जाएगा।

→ सरकार भी IFC पर अपनी सीमाओं के चले देवाव नही जान पाएगी अतः IFC पूर्ण जवाबदेह होकर अर्थव्यवस्था के हित में जिम्मेवारी ले उर्तियों का निर्वहन करेगा

अतः IFC की आवश्यकता सरकार की विहीन स्थिति की मजबूती के लिए आवश्यक है

2. Recognizing the potential of exports in generating employment, a number of steps need to be taken to address India's weakening export competitiveness. Analyze. (150 words) 10

रोजगार सृजन हेतु निर्यात क्षेत्र की क्षमताओं की पहचान करते हुए, भारत की कमजोर होती निर्यात प्रतिस्पर्धा को संबोधित करने हेतु कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

निर्यात क्षेत्र आज भी भारत में क्षमता से कम रोजगार सृजित कर रहा है।

निर्यात क्षेत्र की क्षमताएं :-

→ यह क्षेत्र 40% योगदान MSME क्षेत्र से प्राप्त करता है। इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

→ भारत का विशेष अर्थिक क्षेत्र (SEZ) अपनी क्षमता से कम उपयोग में आ रहा है। कुल 335 SEZ में से 223 ही संचालित हैं। यहां व्यापक रोजगार उत्पन्न हो जाता है।

→ विदेश व्यापार नीति (2015-20) का क्रियान्वयन सफ़र नहीं हो पाया है। इससे रोजगार बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है।

→ सरकार को उत्पाद विविधिकरण, गैलरी विविधिकरण

आदि का परिचालन सुचारु रूप से नहीं कर पाई।

निर्यात उत्पत्ति हेतु आवश्यक कान

- 2020 में अपेक्षित सुधार होने चाहिए।
बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें लागू हो।
- EXIM बैंक निर्यात इकाइयों को विशेष
फैलाव देकर उन्नत बनाए।
- MSME क्षेत्र को मजबूत किया जाए।
- वैश्विक स्तर पर उत्पत्ति देशों से निपटने
हेतु सरकार सहितगी, प्रदूषण, निर्यात सुविधाएं
आदि प्रदान करें। जहाँ - अफ्रीका, मध्य एशिया में।
- सरकार व उद्यमियों के बीच निर्यात कठिनाई
नीति हेतु पारस्परिक बातचीत हो। अत्यंत निश्चिंत
होना मिले।
- जीटी डिपेंडेंस, जीटी इमेज उद्योगों पर जोर
दिया जाए।

कतः। संस्थागत व मानविक स्तर पर सुधार
करके भारत के निर्यात को बेहतर बनाया
जा सकता है।

3. Highlighting the main features of National Mineral Policy, 2019, discuss how it can help in ensuring sustainable and responsible mining.

(150 words) 10

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, चर्चा कीजिए कि यह संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करने में कैसे सहायता कर सकती है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019, राष्ट्रीय खनिज नीति-2008 को प्रतिस्थापित करेगी तथा सभी हितधारकों को सम्बोधित करती है।

विशेषताएँ

- खनिज को 'उद्योग' का दर्जा प्रदान करती है।
- निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है।
- जिला खनिज कल्याण निधि का उपयोग खनिज प्रक्रियाओं के लिए करने हेतु प्रत्‍यक्षी रूप से करती है।
- संधारणीय खनिज क्षेत्रों का प्रावधान करती है।
- खदान लाइसेंस प्रक्रिया को उधार बनाया गया है।
- विशेष खनिज क्षेत्र (ELZ) का प्रावधान करती है।
- उद्योग-आधारित सहयोग को बढ़ावा देती है।
- खनिज उत्पाद धारकों को पड़े आदि की व्यवस्था परामर्शों बनाती है।
- अंतर-परीक्षण समता की बात करती है।

संघारणीय व उत्तरदायित्व खनन की सुनिश्चितता

- इसमें पर्यावरण का बहुत प्रावधान है ताकि जनितों से खनन प्रक्रिया, हास-पास के लोगों को कोई हानि न हो।
- इसमें कंटेनर-पीकिंग-लगाता की प्रावधान है जो भारी पीकिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखता है।
- संलग्न प्रक्रिया की कल्पना 'दिल जनित कल्पना विधि' से होगी।
- खनन प्रक्रिया के लिए बीमा की प्रावधान भी है।
- यह सभी पर्यावरणीय बातों भचा गया, वन संरक्षण कायदा, 2006 कायदा के अनुसार ही चलाया जाएगा।

कब: इस नीति से उत्तरदायित्व के साथ ही संघारणीय खनन सुनिश्चित होगा।

4. Highlighting the salient features of the PM JI-VAN Yojana, analyze how it can assist in achieving the vision and goals of the National Policy on Biofuels, 2018. (150 words) 10

“प्रधानमंत्री जी-वन योजना” की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, विश्लेषण कीजिए कि यह जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति, 2018 की दृष्टि और लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना :-

- यह वन क्षेत्रों के उत्पादों एवं अन्य जैव पदार्थों के उच्च मात्रा के रूप में जैव ईंधन हेतु प्रोत्साहित करती है।
- इसमें अप्रयुक्त एवं बंजर भूमि का उपयोग जैव-ईंधन उगाने हेतु किया जाएगा।
- आदिवासियों को वन-उत्पादों का मूल्य दिलाते हुए आम के तह में वारत करती है।
- इसमें रतनपोते, मक्का, जल्ला आदि को बढ़ावा दिया गया है।

जैव-ईंधन राष्ट्रीय नीति - 2018 के कर्तव्य

- यह नीति जैव-ईंधन को बढ़ावा देती है तथा इसे नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत मानती है।

→ प्रधानमंत्री जी-वन योजना के उत्पाद इस नीति में अच्छे मास के रूप में एवं पर्याप्त उपलब्धता के साथ सहायता करेंगे।

→ यह परिवर्ण कृत्रिम ईंधन का एंजी वही लक्ष्य के रूप में बाजार भी उपलब्ध कराएगी।

→ ये योजना व नीति परस्पर पूरक हैं तथा एक-दूसरे को सिंच करते हैं।

कतः जी-वन योजना के तहत जैव-ईंधन नीति को प्राप्त होगा।

5. Zero Budget Natural Farming (ZBNF) provides an alternative to capital and chemical intensive agriculture currently being practiced in India. Analyze.
(150 words) 10

जीरो बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF), भारत में वर्तमान समय में प्रचलित पूंजी और रसायन गहन कृषि का एक विकल्प प्रदान करती है। विश्लेषण कीजिए।

जीरो बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF) से तात्पर्य
है कि बिना रासायनिक उर्वरकों के स्थानीय
जैविक खाद के आधार पर कृषि करना।

वर्तमान कृषि के विकल्प

→ वर्तमान कृषि में लागत ज्यादा है। उर्वरक महंगे
हैं तथा बीज भी महंगे उपलब्ध है। इस
कारण अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है।
जबकि ZBNF लागत को शून्य करती है
केवल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बीज को
प्रयोग में लाती है।

→ ZBNF में कुछ पानी की जरूरत है
ज्यों कि तंगर मिट्टी ज्यादा सिंचाई आवश्यक
मानती है। जबकि भारत जैसे कम वर्षा वाले
क्षेत्र में यह अच्छा विकल्प है।

- ZBNF पर्यावरण - अनुकूल है। इससे व नो मुदा प्रदूषण होता है और न ही जल प्रदूषण। अतः वर्तमान स्ति ले बेहतर है।
 - यह भूमि की उर्वरा क्षमति को बचाए रखती है। स्थानीय गोबर खाद को प्रयोग में लाती है। इस कारण स्वयं पर ही निर्भर है।
 - ZBNF भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, इस वर्ष वाले क्षेत्र में बेहतर साबित होगी क्योंकि वहां आवश्यक स्थानीय परिस्थितियां उपलब्ध हैं।
 - लघु व सीमांत किसानों के लिए ज्यादा आकर्षक है।
 - ZBNF उत्पादों की 'ब्रांडिंग' करके जिनके उत्पाद के बतौर निर्यात हो सकेगा।
- अद्यपि ZBNF की उत्पादकता कम है परन्तु इसमें सुधार करके शर्तः शर्तः इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

6. Marine life is facing 'irreparable damage' from the millions of tonnes of plastic waste which ends up in the oceans each year. In this context, examine the implications of plastic pollution on marine ecosystem and suggest some measures for addressing this problem. (150 words) 10

समुद्री जीवन, प्रति वर्ष समुद्र में पहुँचने वाले लाखों टन प्लास्टिक कचरे के कारण 'अपूरणीय क्षति' का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए और इस समस्या के समाधान हेतु कुछ उपाय सुझाइये।

प्लास्टिक कचरे से समुद्री मछलियाँ व अन्य जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। उदा० - पेलिडिकी गरबेज

⇒ यह क्षति अपूरणीय है क्योंकि इस प्लास्टिक के कारण खराब हुए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता।

प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव

→ समुद्री जीव-जन्तु इसे निगत जाते हैं। इससे वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

→ इन मछलियों का प्रयोग करने पर मानव स्वास्थ्य पर उत्पन्न प्रभाव पड़ता है।

उदा० - मिनामेटा दुर्घटना (जापान)

- इससे समुद्री बीछ (तर) पर कचरा जमा हो जाता है। वे पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं
- समुद्री कचरा समुद्री जीवों की दुर्घटना का कारण बन सकता है।
- समुद्री खाद्य श्रृंखला प्रदूषित हो सकती है जिसके गंभीर परिणाम होंगे।

समाधान

- प्लास्टिक को धीरे-धीरे पूर्णतः प्रतिषेधित करना चाहिए।
 - जनता को इसका उपयोग न करने हेतु जागरूक किया जाए।
 - 'ब्लू प्रिंसेज तरिफिकेशन' जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर सभी समुद्री जीवों की सुरक्षा हो।
 - वैश्विक स्तर पर अति लक्ष्मण बने बिना प्रभावी रणनीति तैयार करना।
- अतः सरकार व जनता दोनों मिलकर देश को हरा निवास बनाते हैं।

7. Write a short note on the evolution of Bharat Stage norms in India. Also discuss the significance and challenges posed by the planned introduction of BS-VI norms in India from the year 2020. (150 words) 10

भारत में भारत स्टेज मानकों के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साथ ही, वर्ष 2020 से भारत में BS-VI मानकों को योजनाबद्ध रूप से लागू किए जाने के महत्व और उसमें आने वाली चुनौतियों की भी चर्चा कीजिए।

भारत स्टेज - VI मानक यूरो मानक - VI की
तर्ज पर उच्च गुणवत्ता युक्त ईंधन के
प्रयोग से लाते हैं ताकि प्रदूषण कम हो।

विकास :-
→ अभी भारत में सभी शहरों में ब्रास
स्टेज - VI मानक लागू हैं।

→ अन्य ~~सभी~~ स्थानों पर BS-VI का प्रयोग हो
रहा है।

→ भारत लग. 2000 से इसको अपना रहा है

→ भारत ने BS-V को न अपनाया था
BS-VI अपनाने का निर्णय लिया है।

BS-VI को लागू करने का महत्व :-

→ पर्यावरण - प्रदूषण से राहत मिलेगी
वायु - गुणवत्ता, बढ़ेगी।

- स्वतन्त्र लेबन्दी बीमाप्लान का होगा। दिल्ली जैसे शहरों का 'लाइवेलन इंडेक्स' (मुद्रांश)।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत की पर्यावरण प्रदूषण की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा।
- यह उत्पादन के नई संभावनाएँ व रोजगार को बढ़ाएगा।

क्रियान्वयन के चुनौतियाँ

- वर्तमान वाहनों का उपयोग लगातार जारी रखना पड़ेगा क्योंकि कि नए वाहन खरीदना लोगों को मंहगा पड़ेगा।
- BS-IV मानक प्रमुख वाहन के ईंधन के बढ़ावा देना होगा।
- वर्तमान ओएडो कंपनियाँ वाहन निर्मित कर करेगी क्योंकि उन्हें खरीदने वाले नहीं होंगे। इन्हें बेटी पड़ेगी।
- सामान्य जनता इन मानकों के बारे में अनभिज्ञ है। इस जागरूकता बढ़ानी होगी।

अतः इन चुनौतियों को हल करके BS-IV को प्रोपगण्डा तरीके से लागू करना चाहिए।

8. What are black holes? Highlight the challenges in imaging a black hole? How were these challenges overcome by the Event Horizon Telescope project? (150 words) 10

ब्लैक होल क्या हैं? ब्लैक होल के चित्रण (इमेजिंग) में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप प्रोजेक्ट द्वारा इन चुनौतियों को कैसे दूर किया गया?

ब्रह्माण्ड में उपस्थित वे पिण्ड जो अपनी
अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते हर
किसी चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं, ब्लैक
होल कहलाते हैं।

→ सुपरनोवा के अंतिम विकारात्मक रूप में
इसका निर्माण होता है।

इमेजिंग में चुनौतियाँ

→ चूंकि यह प्रकाश किरणों को भी अवशोषित
कर लेता है। इस कारण इसके कोई किरण
निकल चुम्बरे तक नहीं पहुँच पाती हैं, अतः
यिसे नहीं लिखा जा सकता है।

→ अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
तन्नी तरंगदैर्घ्य की इतनी लम्बाई हो
जाती है। अतः चित्रण मुश्किल है।

इवेंट होराईजन टेलीस्कोप प्रोजेक्टर :-

→ इवेंट होराईजन वह क्षेत्र है जो इतने
अंधी दूर पर होता है तथा इतने चरों को
चमकत लगाता है। कतः इस टेलीस्कोप में
इस क्षेत्र का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए -
होरा का चित्रण किया जाता है।

→ यह टेलीस्कोप इवेंट होराईजन क्षेत्र
का रेखीय चित्रण प्राप्त कर पाता है।

9. While mentioning the objectives of the Arms Trade Treaty (ATT), discuss the challenges which are hindering the utilization of the ATT to its full potential. (150 words) 10

शस्त्र व्यापार संधि (ATT) के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए, उन चुनौतियों की चर्चा कीजिए जो ATT को इसकी पूर्ण क्षमता से उपयोगित किये जाने में बाधक हैं।

शस्त्र व्यापार सन्धि वैश्विक तौर पर हथियारों के व्यापार के आधार-निम्न बताती है।

उद्देश्य

- यह परमाणु हथियारों जैसे शस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाती है।
- परम्परागत हथियारों के व्यापार को आसन्न रहा व शांतिपूर्ण उपयोग हेतु नियंत्रित करती है।
- दुर्गर सन्धियों के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करती है। उदा. - अहम कोटिया
- ATT उपयुक्त बाजार तंत्र की निर्माण करती है तथा निरोधक के तौर पर हथियारों के भ्रष्ट प्रयोग करती है।

युनोटिमा

- शक्तिशाली राष्ट्रों का मनभागा रचना
इसके डिप्लोमेट के बाधक है।
- चीन एक राष्ट्र को राष्ट्रीय हितों के अन्तर्गत
भी काम करेंगे। वे लक्ष्य को दृष्टिगत
करेंगे।
- 95 लक्ष्य देशों के पारस्परिक नातेबंद
नहीं है।
- दक्षिण एक बड़ा बाजार है जहाँ
आर्थिक लाभ इन प्रायश्चित्तों को करने के
सोकेगा।
- लक्ष्य के निहित स्वार्थ इसे द्वारा
होने में सहायक करेंगे।

अतः विभिन्न युनोटिमा है जो इसके
वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के
सोकेगी।

10. Threats to internal security of India may be posed both through the communication networks and also to the networks. Discuss. Also, highlight the steps taken by the government in making the networks more secure.

(150 words) 10

भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा संचार नेटवर्कों के माध्यम से एवं स्वयं संचार नेटवर्कों को खतरा होने, दोनों ही प्रकार से हो सकता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, नेटवर्कों को अधिक सुरक्षित बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए।

वर्तमान में संचार नेटवर्क एवं इसके माध्यम से खतरा ज्यादा होता जा रहा है जो एक आतंक व उग्रवादी रास्ता है जहां से इस देश को क्षति पहुंचाई जा सकती है

संचार नेटवर्क के माध्यम से:

- इसके हैकिंग, लूटिंग, रैनेजिंग, जाल चोरी आदि शामिल हैं
- हैकिंग से जो हैक करना
उदा - बांग्लादेश (2016)

स्वयं संचार नेटवर्क पर:

- रक्षा नेटवर्क पर हमला करने सेक करना
- दूरसंचार नेटवर्क में लक्ष्य पैदा करने से विशेष के डिस्कने करना आदि

ये दोनों ही रास्ते ले जाने वाले देश के बड़े-बड़े
मिडल क्लास लोगों को इस कारण अपराधियों को
पकड़ना मुश्किल है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- आपतकालीन प्रतिक्रिया हेतु CERT-In का
गठन किया है तथा विभिन्न एजेंसियों हेतु CERT-in
का गठन किया है।
- 2014 में राष्ट्रीय लार्वर सुरक्षा लक्षणक सेट का
गठन किया है।
- इंटरलॉक को 'नेशनल क्रिप्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर'
के अन्तर्गत किया है।
- रक्षा क्षेत्र का प्रत्येक लॉन्चर नेटवर्क है।
- NTRC (राष्ट्रीय तकनीकी कन्ट्रोलिंग सेंटर) की
स्थापना की गई है।
- साइबर सुरक्षा एक्ट - 2008, साइबर सुरक्षा नीति
2013 को बनाया है।
- कतः विविध सरकारी उपाय व नवविचार
इस एजेंसी से उठाए जा रहे हैं।

11. Highlight the importance and challenges related to integration of Variable Renewable Energy (VRE) in India. Mention some steps that can be taken for its smooth integration with the synchronized Indian grid. (250 words) 15

भारत में परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (VRE) के एकीकरण के महत्व और इससे संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ऐसे कुछ कदमों का उल्लेख कीजिए जो समक्रमिक (सिंक्रनाइज्ड) भारतीय ग्रिड के साथ इसके सहज एकीकरण के लिए उठाए जा सकते हैं।

भारत में परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (VRE)
का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। यह पर्यावरण
अनुकूल ऊर्जा है।

एकीकरण का महत्व

- इससे तापीय ऊर्जा लंबे दूरी पर आराम
होगा तथा इस नवीकरणीय ऊर्जा की पहुँच
'लम्बी श्रृंखला' तक होगी।
- VRE का उचित हल प्राप्त होगा। यह
पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा होने के साथ-साथ देश
- भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्धताओं (IWDG)
का पूरा करेगी।
- इससे लम्बी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए
आवश्यक नीति निर्माण, विधानमंडल, विचार-
विमर्श संभव होगा।

चुनौतियां :-

- VRE का निर्माण अभी भी बहुत ही दूर है। यह आवश्यक मांग का (फि-पोषण) ही पूरा करती है।
- तृतीय (दूर) पर उच्च लागत वाले उपकरण मुख्यतः आयात किए जा रहे हैं (भीत ले)
- यह ऊर्जा विभिन्न स्रोतों अथा-पवन, लोह, ज्वारीय, भूतपीठ आदि में विकसित हो रहा है तथा भौगोलिक अंतराल ज्यादा है इस कारण एकीकृत नहीं है।
- अभी पृथक ग्रिड निर्माण करना ज्यादा खर्चीला होगा।
- निवेश अभी भी बल स्रोत में '5n है।
- ताप-ऊर्जा सुरक्षात्मक रूप ले (तकनी है) इस कारण इतना महंगा होगा कि उपयोग की तरह बचेगा।

समझाते भारतीय ग्रिड के साथ एकीकरण

→ सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रिड के साथ संयोजित किया जाए। उदा. - तटीय क्षेत्रों की पवन ऊर्जा का पश्चिमी ग्रिड के साथ संयोजन।

→ स्थानीय स्तर पर एकीकरण होने पर इसे राष्ट्रीय ग्रिड से संयोजित करके एक स्थान स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित किया जा सकता है।

→ जहां और-नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता है। वहां इसे पहुंचाया जाए।

ऊर्जा राष्ट्रीय ग्रिड से संयोजित करके इच्छित व्यापक स्तर पर वित्तित किया जा सकता है।

12. There have been arguments that India could fall into a 'middle income trap'. Explaining the phenomenon, highlight the reasons behind such arguments. How can India avoid it? (250 words) 15

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि भारत 'मध्यम आय पाश' में फँस सकता है। इस परिघटना की व्याख्या करते हुए, ऐसे तर्कों के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत इससे किस प्रकार बच सकता है?

मध्यम आय पाश में 1997 में एशिया के कई देश फँसे थे। भारत ने भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था।

मध्यम - आय पाश परिघटना :-

- जब देश के अग्रदूत जनसंख्या वृद्धि हो रहे
- कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध नहीं है
- लोग मध्यम - आय वर्ग से उच्च आय की स्तर पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे
- इससे मांग कम होती जाती है
- मंदी की दशा उत्पन्न होती है

भारत के लिए उत्तरदायी कारण

- भारत में रोजगार की कमी, जनसंख्या का बढ़ना, विकासशील अवस्था आदि कारण हैं जो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।

- सरकारी ज्यादा उच्च स्तरीय भांग उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। मद्यक वर्ग ज्यादा है जो अपने काम को उच्च स्तर वर्ग में स्थापित नहीं कर पाया है।
- भारत में जनसांख्यिकीय वितरण असमान है जो अपातक रोगों पर कुशलता से रोकथाम का प्रभाव नहीं होता। इसे स्थिति में ले जा सकता है।
- उद्योगों में भांग लगाता नहीं कर पा रही है। इस कारण भंडी चली स्थिति आ सकती है।
- निवेश कम है। बाहरी कर्तव्यवाह भी धीरे-धीरे कम हो रहा है।
- विकास दर में गिरावट है। वहीं निरक्षर लोगों की असुरक्षित नीतियों की प्रभावित करती है।

ये सब स्थितियां भारत को इस जगह में फंसा सकती हैं।

बचने के उपाय :-

- निजी व तार्वजिक बनाना होगा।
 - 'मेक-इन-इण्डिया' व 'स्क्रिप्ट - 'इण्डिया' को तब बनाना होगा।
 - आर्थिक विकास पर ध्यान देने सरकार व RBI को दृष्टिकोण करेंगे।
 - श्रम विभागों में सरकारी, अनुभव व संरचना का हि आवश्यक है।
 - विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा।
 - वैश्विक स्तर पर सहयोग ले FDI व FPI बढ़ाई जानी चाहिए।
 - घरेलू भांग उपलब्ध करनी होगी।
- अतः सभी शिक्षाओं में प्रयास करें
माध्यम इस स्थिति में बाहर आना है कि
ले क्या संभव है।

13. Highlighting its importance, discuss the major issues that plague effective monetary policy transmission in India. Also, mention the steps taken by RBI to improve it. (250 words) 15

भारत में मौद्रिक नीति संचरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए जो इसकी प्रभाविता को बाधित करते हैं। साथ ही, इसमें सुधार के लिए RBI द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

मौद्रिक नीति संचरण से तात्पर्य है कि RBI द्वारा किए गए नीतिगत परिवर्तनों का प्रभाव लाभान्वित जनता तक पहुँचे। उदा - रेपो दर घटाने पर बाजार दर में कमी।

मौद्रिक नीति संचरण के महत्व :-

- इससे RBI के नीतिगत निर्णयों का प्रभाव अर्थव्यवस्था तक त्वरित पहुँचता है।
- RBI की नीति-निर्देशन व विनियामकीय शक्ति का प्रभावी परिणाम प्राप्त करने का साधन है।
- जनता को भी 'ईज नीति' में राहत मिलती है।
- प्रभावी निर्णय - उम्मीद संचरण हो पाती है।

बाधित करने वाले कारक

→ बैंक इसे आसानी से ग्रहणों तक स्थापित नहीं करते हैं।

उदा: जब RBI रेपो दर बढ़ाता है तब तो सुरक्षा लाभ दर बढ़ा देते हैं परन्तु इस कारण पर बैंक कम नहीं करते हैं।

→ बैंकों का बहुत NPA उन्हें ऐसे सावधानी का काम उभाने हेतु प्रेरित करता है।

→ बैंकों का लक्ष्य 'लाभ' करना है। जब वे लाभ के लिए उ-प माह वास नीति का प्रयोग ग्रहणों तक लंचर करते हैं।

→ भारत में ज्यादातर विदेशी क्षेत्र बैंकों से प्राप्त है। जब: बैंक ही मोहिनी नीति लंचर का प्रमुखी रास्ता है।

→ RBI द्वारा कोई दृष्टांतक शर्तवाही के होने से पत्राग वीक ले नहीं होती है।

→ बैंकों की लाभ दर, रेपो दर से प्रभावित नहीं पड़ी है।

RBI द्वारा उठाए गए कदम :

→ RBI, MCLR को अपना रहा है
बैंकों को ब्याज पर रेपो पर ले लम्बवर्ष
मुदती है।

→ पावना नहीं करने पर प्रभुत्व की कार्रवाई
का आवधान है।

→ RBI द्वारा समय, समय पर निगरानी
रखते हुए एक रेंज प्रदान की जाएगी ताकि
बैंक उस सीमा में तक जितना तक पहुंचाए

इस तरह RBI नीतिगत व कार्रवाई में
माध्यम से इसे प्रभावी बना रहा है।

14. Highlight the constraints faced by rainfed agriculture in India. Discuss some agronomic practices that can be adopted for stabilizing agricultural production in rainfed areas. (250 words) 15

भारत में वर्षा सिंचित कृषि में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु अपनाई जा सकने वाली कुछ कृषि-वैज्ञानिक पद्धतियों की चर्चा कीजिए।

भारत में समतल इषि क्षेत्र का 50% से ज्यादा क्षेत्र वर्षा सिंचित है। यह विविध समस्याओं से जूझ रहा है।

बाधाएं :-

- सरकार की नीतियां मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों को ध्यान में रखी हैं तथा उन्हें जमीन क्षेत्रों पर एक समान रूप से लागू किया जाता है।
- ये क्षेत्र शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां सिंचाई कम है। इससे उत्पादन कम है।
- इन क्षेत्रों में मुख्यतः दालों का उत्पादन होता है जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का प्रावधान नहीं है।
- बाजार तक पहुंच का अभाव, परंपरागत

इसि पइतिषां , मूल्य वर्धन नहीं , पराप्ति प्रथम
नुविद्यामों की अभी साक्षि कायक है जो बाधक है

इसि उत्पादन हेतु इसि-वैज्ञानिक पइतिषां

- ⇒ मोटे अनाजों की खेती करनी चाहिए।
- ⇒ इस ~~का~~ लिचार्ज की आवश्यकता वारे बीजों का प्रयोग है।
- ⇒ रत्नजीत जैसे खेती करने प्रभावी लाभ कमाया जा सकता है (जैव-ईंधन)
- ⇒ खेती की परती इस्तेमाल वर्षाजल की नमी को संजित किया जा सकता है।
- ⇒ मल्लिचंग (mullching) लेनी जरूरी नहीं संरक्षित हो सकती है।
- ⇒ अवनसिमा अपरदन को कम करने हेतु खेत में जुताई करना बंदि नहीं करी रहा।
- ⇒ सीमिटाइ इसि , सुंदर लजिंग ले भ्रष्ट अपरदन कम करने इसि की जा सकती है।

- श्वि के साथ पशुपातक उरके उनके गोद
को खास के रूप में प्रयुक्त करना।
- कमत बीम के को उपनान ताकि विपक्षि
स्थिति में राहत प्राप्त हो सके।

कतः विविध उपायों व श्वि-वेबानि पद्धति
से उत्पादन स्थिर रखा जा सकता है।

15. Despite the steps taken by the government in recent years, a number of problems continue to persist in the urea sector in India. Discuss. What reforms should be taken to address the persisting problems?

(250 words) 15

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद, भारत में यूरिया क्षेत्र में कई समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। चर्चा कीजिए। मौजूदा समस्याओं के समाधान हेतु क्या सुधार किए जाने चाहिए?

भारत में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण यह दुनिया में लिए आवश्यक रासायनिक उर्वरक है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

भारत क्षेत्र की समस्याएं

- भारत उत्पादन, मांग की तुलना में कम है
- इसकी वस्तु की बांग्लादेश व नेपाल तक होती है
- इसका या सरकार तबिली होती है जो लक्ष्मी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को प्राप्त होती है परन्तु वहां प्रचारा ज्यादा है
- भारत के प्रयोग से भूमि पड़कप लगाता सब रखा है कई जगह गू-पल के भारत का प्रभाव है। वहीं भूमि में भी भारत पर निरंतरता बढ़ती जा रही है
- नीम-कोटेड भारत हर जगह नहीं है

समाधान

- श्रुति के लिए तबिली DBT (युलन-तलन हल्ललन) ले ढलत हो तलल ठललल हल ढल ढल हललनलं को हलले। हले ढललललल क तललरी ढल रोके लगेली।
- हलल ले हलर हललल ढलढोग रोके हले नील-कोले श्रुतल हलललल हो।
- श्रुतल कल नलललल ढलढोग हो। हलल-लललल-हल के हलललल हललल ढलढोग हलल ढलल।
- श्रुतल ढलललन हललललं कल वललेडुलल हो।
- हलल की हललललल ले हलले ढललललल लुनलललल हो।
- हललल व ढलललल हललललं के लील तलललल हो तलल ढलली वललल लुनलललल हो लले।

कहा इन उपायों से निरोधात्मक व
उपचारात्मक दोनों उपायों से पूरिमा से
ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

16. What is Access and Benefit Sharing? Explain how it aids in sustainable use of biodiversity. Also, mention the different global and national level mechanisms for ensuring Access and Benefit Sharing. (250 words) 15

पहुंच और लाभ साझाकरण (एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग) क्या है? यह जैव विविधता के संधारणीय उपयोग में किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। साथ ही, पहुंच और लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रणालियों का उल्लेख कीजिए।

पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) से तात्पर्य है
कि जैविक उत्पादों के उपयोग से निर्मित
उत्पादों के लाभों का हिस्सा स्थानीय निवासियों
तक जाना चाहिए अर्थात्, कंपनियां जहां
से वन या वन्य उत्पादों का सहारा लेते
हैं, वहां जाकर लाभ उठाएंगे। वहां के वनवासी
भी इससे लाभान्वित हों।

जैव विविधता के संघारणीय उपयोग के लक्षण

- जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा क्योंकि स्थानीय स्तर पर लाभ प्राप्त होने से लोग उन जीवों या पौधों की संरक्षा रखेंगे।
- यह उत्पादों का उपयोग सिर्फ लाभ के

करे करने से रोकेगा तथा नैतिक दायित्व
आरोपित करते हुए कंपनी को पाबंद करेगा
कि लाभ पर्यावरण संरक्षकताओं को भी मिले।

- ~~क~~ स्थानीय निवासी उचित लाभ प्राप्त करें
संरक्षण हेतु ज्यादा प्रेरित होंगे।
- अंधाधुन दोहन को रोका जा सकेगा।
- ~~बिना~~ निगरानी सतत बनी रहेगी।

वैश्विक स्तर पर प्रभावितियां

- ' कार्टेजियन प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी '
इस दिशा में महत्वपूर्ण काम है जो जैव
विविधता संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- वायो-डायवर्सिटी पर कन्वेंशन ऑफ पार्टीज
(COP) का नियमित आयोजन इस
दिशा में नीति-निर्माण हेतु आवश्यक
मंच है।
- IUCN की इस दिशा में लगातार कार्य
चल रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर:-

- वन क्षति प्रतिस्तरक कोष (CAMPA) की निर्माण स्थानीय नागरिकों की राय पहुँचाता है
- राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम-2002 महत्वपूर्ण हैं।
- वन्यजीव संरक्षण बोर्ड की उद्यानमंत्री की अध्यक्षता में प्रभावी कार्यवाही करता है
- विभिन्न NGOs की सह दिशा में कार्य करता है
उदा - ग्रीनपीस

→ अतः राष्ट्रीय व वैश्विक दोनों स्तर पर प्रभावकारी है।

17. Stating the significance, discuss the challenges in achieving disaster resilience of infrastructure. Suggest some ways for mainstreaming it in the development paradigm. (250 words) 15

अवसंरचनाओं का आपदाओं के प्रति सुनम्य (रेजिलिएंट) होने के महत्व को स्पष्ट करते हुए, इससे संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इसे विकास प्रतिमान की मुख्यधारा में लाने हेतु कुछ उपाय सुझाइये।

अवसंरचनाएं आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाती हैं परिणामस्वरूप आपदा जन-धन की हानि होती है।

सुनम्य होने का महत्व

- आपदा का प्रभाव कम विनाशकारी होता है। जन-धन की हानि कम होती है।
- अवसंरचना को कम नुकसान पहुंचता है।
- क्षतिग्रस्तता कम होती है पुनर्निर्माण में
- कठिने बिना किसी अर्थ के क्षति
- कार्य कर सकेगा है।
- सुरक्षा के प्रति जागरूकता हुआ जा सकता है।

पुनर्निर्माण

- इसके लिए विभिन्न आपदाओं

के संदर्भ में लिम. लिम. अधोलंघन आवश्यक है जैसे - गुरु, डाटा रचना, बाद डाटा आदि समन्वय करने इस अधोलंघन का निर्माण चुनौतीपूर्ण है।

→ उच्च तकनीकी की आवश्यकता है जो भारत में उपलब्ध होना मुश्किल है।

उदा० - जापान की गुरु के तकनीकी अधोलंघन।

→ लागत ज्यादा है, अतः सामान्य आदमी इस तकनीक को नहीं अपना सकता है।

→ क्षेत्रीय विविधताओं के कारण आपदा भी बहुत-बहुत है। अतः नीति-निर्माण की राज्य सरकारों के समन्वय में होना है।

विकास प्रतिमान में लाने हेतु उपाय

→ प्रवन-निर्माण संस्था बनाकर इसकी आवश्यकता सुनिश्चित की जाए।

→ इस लेखिता में आपका मे अग्रहा परिभाषा का निधारण हो।

→ वैश्विक सहयोग लोक तकनीकी युद्ध का जाए। उदा - जापान ले अग्रोपरोधी।
- अमेरिका ले तुष्टान रोधी।

→ जनता को जागरूक किया जाए ताकि वो स्वयं इसे अपनाए।

→ सरकार तकनीकी व आर्थिक प्रोत्साहन दे सकती है।

→ राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों का साथ लेकर बेड सरकार शुरू। मॉडल का 'बन' काए।

कतः विभिन्न उपायों ले इसे अद्योतन्यता निर्माण में शामिल किया जा सकता है।

18. Highlighting the significance of data localization for India, discuss various challenges associated with data localization. (250 words) 15

भारत के लिए डेटा के स्थानीयकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डेटा के स्थानीयकरण से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

डेटा के स्थानीयकरण से तात्पर्य है कि डेटा जहां उपलब्ध होता है, उसका भंडारण भी उसी देश में किया जाए।

RBI ने भुगतान के लिए डेटा स्थानीयकरण पर बल दिया है।

महत्व

- डेटा की सुरक्षा व निभेक्षण आसानी से स्थापित हो सकता है।
- डेटा विदेशों में संरक्षित होने से भारतीय पर्सनलिटी का डेटा सुरक्षित होता है।
- बी.एन. ब्रज्ज लक्ष्मि ने भी डेटा स्थानीयकरण पर बल दिया है।
- डेटा चूंकि निजी व गोपनीय जानकारी रखता है अतः इसके देश में भंडारण सुरक्षा ले (समझोता) है।

→ विदेशों में डेटा दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं।

उदा- फेसबुक द्वारा हंगेरिका को डेटा डेर
युनाय के इस्तेमाल।

स्वाधीन्यकरण के प्रमुख चुनौतियाँ

→ वैश्विक दूधपेयन के बढ़ते मामलों से
लम्बी डेटा का स्वाधीन्यकरण करना चुनौती है।

→ कंपनियों को मेजबान देश में सर्वर
स्थापित करना पड़ेगा। उसी लागत
ज्यादा आधमी।

→ यह 'बढ़त आओ इंडिया बिजनेस' के
विपक्षी होगा।

→ विदेशी स्टार्ट-अप धरा गिरेश
के प्रतिष्ठित होगा।

→ भारत को विदेशी मामलों में अलग
रूप लम्बता है।

→ सरकार की डेटा तक पहुँच बढ़ेगी। इसके

पुनः निजता सम्बन्धी मामले उठेंगे।

→ चूंकि डेटा ज्यादातर 'जनसिपिरेड' होता

है। इस कारण कंपनियाँ सरकार से लाभ

शेयर नहीं का सकते। इसलिए: स्थानीयकरण

का मोर्चा चला नहीं होगा।

→ कंपनी अन्य देशों में अपना निवेश स्थगित
कर सकती है।

उदातः विभिन्न चुनौतियाँ इसके स्थानीयकरण
में बाधक हैं।

19. Money Laundering as a socio economic offence is a menace especially for developing countries like India. Comment. What measures have been taken at the domestic and international levels to deal with this menace?

(250 words) 15

एक सामाजिक आर्थिक अपराध के रूप में धन शोधन विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक खतरा है। टिप्पणी कीजिए। इस खतरे से निपटने हेतु घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं?

धन शोधन से अंतर्गत अवैध रूप से
धन का स्थानांतरण दूसरे देशों में होता है।
यह एक सामाजिक आर्थिक अपराध है।

सामाजिक अपराध

- देश का धन बाहर जा रहा है जो समाज के कल्याण के लिए प्रयुक्त हो सकता था।
- गरीब-झातील का कंटा बच रहा है
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रतिफल भय के प्रभावित होती हैं
- आतंकवादी इतका उपयोग कर सकते हैं

आर्थिक अपराध

- सामाजिक कल्याण को प्रभावित है
- बला धन है। उस अपव्यय किया गया है
- अवैध रूप से धन का स्थानांतरण होता है

क्र. ६८ लाभप्रति - आर्थिक अपराध है

घरेलू स्तर पर उपाय

- धन-शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत गया है तथा ईबोई अवधान किए गए हैं।
 - पैन-आई को आधार-आई ले लिंक किया गया है।
 - 50,000 ₹ से ऊपर के ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से या डिजिटल किए जाते हैं।
 - युनानी बैंक ताकि राजनीति में अप्रयोग को रोक दिया है।
 - सरकार व RBI दोनों इस दिशा में विभिन्न एजेंसियों से उदा प्रशम उदा जनातिनि करती है।
- क्र. ७ घरेलू उपाय हवावा, धन शोधन आदि पर रोक लगाईगी।

इंटरव्यू पर उत्तर पत्र उपाय

→ धन की राउण्ड ट्रिपिंग रोकने हेतु विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग व सूचना साझाकरण।

→ दोहरा कराधान पहिचान लाभस्रोत (DITA) में त्रुटिपूर्ण कटे मोनिटरिंग व रिपोर्टिंग के साथ वफा लाभस्रोत।

→ इंटरपीट व अन्य लेम्बाको के सूचना प्राप्त।

→ 4-20 देशों के साथ वार्षिक सहयोग।

→ डिप्लोमैटिक लाभस्रोत के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करना

अब ये विभिन्न उपाय इसे रोकने में कारगर साबित होंगे।

20. The primary motive of terrorism differs from that of organised crime but there exists a symbiotic relationship between the two. Discuss.

(250 words) 15

आतंकवाद का प्राथमिक उद्देश्य संगठित अपराध के उद्देश्य से भिन्न होता है, किन्तु दोनों के मध्य एक सहजीवी संबंध पाया जाता है। चर्चा कीजिए।

संगठित अपराध में धन को उद्देश्य माना मुख्य।
उद्देश्य होता है - भाव्य पदार्थों की तस्करी।

आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य - सरकार व राज्य
की लंग्रता को चुनौती देना।

⇒ आतंकवादी अपनी तत्वा की (स्यपन) चाहते
हैं अपना इच्छित देश व निहित स्वार्थों
की पूर्ति हेतु धरना को अज्ञात देते हैं।

उदा. - ISIS (सत्ता प्राप्ति
ताहिबात सत्ता प्राप्ति)

भारत में आतंकवाद, देश-प-मौल्य
कशमिरी चाहते हैं

वे ~~अपराध~~

⇒ संगठित अपराध में राज्य को चुनौती

नहीं देते बल्कि चोरी, रिश्वेत धन में अपराध
में लिखते रहते हैं।

सहजीवी सम्बन्ध

→ आतंकवादियों को अपने उद्देश्यों
के लिए धन की जरूरत होती है। यह
धन मुख्यतः लंगरि अपराध के माध्यम
से ही आता है।

अतः लंगरि अपराध, आतंकवाद
का पोषण करता है।

→ लंगरि अपराध में अनेक तरीकों
से देश की सम्पत्ति की चोरी होती है।
जैसे - नशे का कारोबार, भ्रष्टाचार
- दलितों की लूट

इसलिए आतंकवादी एक तरह के पैसा प्राप्त
करते हैं वहीं इसी और देश को।

धारे-धारे मुक्तान की पहंचा रहे है।

→ जाती मुद्रा का प्रचलन करके पाकिस्तान
तमबित आतंगवादी तंगबित अपराध कर
रहे है तथा कार्यलयवाता का प्रचलन
पहंचाने का प्रचार कर रहे है

कतः दोनो के मध्य तदपीवी संबंध
पात्रा पात्रा है।